



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]
No. 223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 1993/आषाढ़ 11, 1915
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 1993/ASADHA 11, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1993

सं. 90/93—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 486(अ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त
उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957
(1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ
पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944
(1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने
पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उत्पाद-शुल्क
पूँजी माल, संघटक और कच्ची सामग्री को (जिसे इसमें
इसके पश्चात् माल कहा गया है), भारत सरकार के उद्योग
मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं.
का. आ. 117(अ), तारीख 22 फरवरी, 1993 द्वारा

नियुक्त अंतःमंत्रालय स्थायी समिति (जिसे इसमें इसके
पश्चात् समिति कहा गया है) द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत
निर्यातोन्मुख स्कीम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सामग्री
प्रीयोगिकी मार्कों में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् एकक कहा
गया है) एकक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सामग्री और प्रक्रिया
सामग्री के विनिर्माण या विकास के प्रयोजनों के लिए लाए
जाते पर,—

- (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम,
1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन
उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क, और
- (ii) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल)
अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा
3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्-
ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से निम्न-
लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती
है, अर्थात्:—

- (क) एकक समिति द्वारा अनुमोदित है ;
- (ख) ऐसे एकक द्वारा विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल उत्पादन के कारखाने से सीधे एकक में लाया जाता है और एकमात्र निर्यात के लिए आश्रयित विनिर्माण में प्रयोग होता है ;
- (ग) ऐसे एकक समिति द्वारा अनुबद्ध अवधि के लिए या ऐसी विस्तारित अवधि के लिए जो समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे माल से पूर्णतः या भागतः विनिर्मित वस्तुओं का भारत के बाहर शत प्रतिशत या ऐसी अन्य प्रतिशतता जो समिति द्वारा नियत की जाए, निर्यात करता है ;
- (घ) भारत में उत्पादित या विनिर्मित और विक्रय के लिए अनुज्ञात उत्पाद-शुल्क माल की निकासी पर ऐसा एकक उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 के निबंधनों के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करेगा ;
- (ङ) उक्त माल का विनिर्माण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 173-ड द्वारा यथा उपांतरित उक्त नियम के नियम 156-क और 156-ख में दी गई प्रक्रिया के अनुसार है ;
- (च) एकक उक्त नियम के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का इस उपांतरण के साथ पालन करती है कि अधिसूचना संख्या 123/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22 जून, 1981 से उपाबद्ध प्ररूप सी. टी. 3 में एक प्रमाणपत्र, उक्त नियम के अधीन विहित प्ररूप सी. टी. 2 में प्रमाणपत्र के स्थान पर, एकक के भार-साधक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा ;
- (छ) शर्त (ग) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, ऐसे एकक उपयोग में न लिए गए माल पर और ऐसे माल से विनिर्मित वस्तुओं पर, बिना अवक्षेपण के और निकासी के समय प्रवृत्त दरों पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करेगा ;

स्पष्टीकरण—

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, पूंजी माल से एकक द्वारा माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कोई संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधन अभिप्रेत है और इसके

अन्तर्गत माल पैक करने की मशीनरी, परीक्षण उपस्कर और अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों के लिए अपेक्षित उपस्कर भी हैं ।

[फा. सं. 354/80/92—टीआरयू]

राजीव शर्मा, अव्वर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 1993

NO. 90/93-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable capital goods, components and raw materials (hereinafter referred to as the goods) when brought in for the purposes of manufacture or development of electronics hardware and software by a unit in Electronics Hardware Technology Parks (hereinafter referred to as the unit) under hundred percent export oriented scheme approved by the Inter-Ministerial Standing Committee (hereinafter referred to as the Committee) approved by the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 117(E), dated the 22nd February, 1993, from the whole of—

- (i) the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944); and
- (ii) the additional duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);

subject to the following conditions, namely :—

- (a) the unit is approved by the Committee;
- (b) the goods required by such unit for the manufacture are brought directly to the unit from the factory of production and are used in the manufacture, meant solely for export;
- (c) such unit exports out of India hundred per cent or such other percentage as may be fixed by the Committee, of article manufactured wholly or partly from the goods for the period stipulated by the Committee or such extended period as may be specified by the Committee;
- (d) on clearances of the excisable goods produced or manufactured and allowed to be sold in India, such unit shall pay duty of

excise leviable on such articles in terms of section 3 of the said Central Excises and Salt Act;

- (e) the manufacturer of the said goods follows the procedure contained in rules 156-A and 156-B of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules) as modified by rule 173-N of the said rules;
- (f) the unit follows the procedure contained in Chapter X of the said rules with the modification that a certificate in form C.T. 3 as annexed to notification No. 123/81-Central Excises, dated the 22nd June, 1981 shall be used by the central excise officer in charge of the unit in place of a certificate in form C.T. 2 prescribed under the said rules;
- (g) on the expiry of the period referred to in condition (c), such unit shall pay excise duty on the goods unused and the articles manufactured from the goods without depreciation and at the rates in force at the time of clearance;

Explanation :—For the purposes of this notification, "capital goods" means any plant, machinery equipment or accessories required by the unit for manufacture of goods and shall include machinery for packing goods, testing equipment and equipment required for Research and Development activity.

[F. No. 354/80/92-TRU]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1993

सं. 91/93—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 487(अ):—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क माल को, (जिसे इसमें इसके पश्चात् माल कहा गया है), जिसका उत्पादन या विनिर्माण भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 117(अ), तारीख 22 फरवरी, 1993 द्वारा नियुक्त अंतः मंत्रालय स्थायी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) द्वारा इस निमित्त अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख स्कीम के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी यंत्र सामग्री प्रौद्योगिकी पार्क एकक (जिसे इसमें इसके पश्चात् एकक कहा गया है) में किया गया तथा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 1992 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की ई भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना

सं. 42 (एन-8) 92-97 तारीख 14 सितम्बर, 1992 के अधीन और अनुसार उक्त एकक में कुल मिलाकर विनिर्मित संघटकों और तैयार माल के उत्पादन के कुल मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक मूल्य तक भारत में विक्रय के लिए अनुज्ञात किए गए हैं, उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 के निबंधनों के अनुसार उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जो प्रत्येक सीमा शुल्क के पचास प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है) जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अधीन भारत से बाहर उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही माल पर, यदि उसका भारत में आयात किया जाता है तो उद्ग्रहीत किया जाता :

परन्तु उक्त माल की बाबत कुल सीमा-शुल्क की रकम मूल्य के पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से या, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अन्य सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगी ;

परन्तु यह और कि उपरोक्त परंतुक को कोई बात ऐसे माल को लागू नहीं होगी जो उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क की शून्य दर से प्रभाव्य है :

परन्तु यह और भी कि मूल्य के पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित शुल्क की रकम उसी अनुपात में प्रमाणित की जाएगी जिसमें उक्त माल प्रत्येक सीमा-शुल्क से प्रभाव्य होता यदि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट न दी गई होती ।

[फा. सं. 354/80/92-टी आर यू]
राजीव शर्मा, अवसर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 1993

NO. 91/93-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 487(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all excisable goods specified in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), (hereinafter referred to as goods), produced or manufactured in a Electronic Hardware Technology Park Unit (hereinafter referred to as the Unit) under the hundred percent export oriented scheme approved in this behalf by the Inter-Ministerial Standing Committee

(hereinafter referred to as the Committee) appointed by the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 117(E), dated the 22nd February, 1993, and allowed to be sold in India upto a value, not exceeding forty percent of the total value of production of components and finished goods manufactured in the said Unit taken together under and in accordance with the notification of the Govt. of India in the Ministry of Commerce, issued under sub-section (1) of section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Ordinance 1992, No. 42 (N-8) 92-97 dated, the 14th September, 1992, from so much of the duty of excise leviable thereon in terms of section 3 of the said Central Excises and Salt Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 50% of each of the duties of customs, which would be leviable under section 12 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with any other notification for the time being in force issued under sub-section (1) of section 25 of the said Customs Act on the like goods produced or manufactured outside India, if imported into India :

Provided that the amount of aggregate duties of customs in respect of the said goods shall not be less than the amount calculated at the rate of 25% ad valorem or the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule, read with any other relevant notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 or sub-section (1) of section 5A of the said Central Excises and Salt Act, as the case may be, whichever is higher;

Provided further that nothing contained in the above proviso shall apply to the goods which are chargeable to nil rate of duty leviable under section 12 of the Customs Act read with any other notification for the time being in force issued under sub-section (1) of section 25 of the said Customs Act;

Provided also that the amount of duty calculated at the rate of 25% ad valorem shall be apportioned in the same ratio in which the said goods are chargeable to each of the duties of customs, but for the exemption contained in this notification.

[F. No. 354/80/92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1993

सं. 92/93—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 488 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और निम्न अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 97/91-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 अक्टूबर, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में तीसरे परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“2. इस अधिसूचना की कोई बात समय-समय पर यथा-संगोहित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 117 (अ) तारीख 22 फरवरी, 1993 द्वारा नियुक्त अंतः मंत्रालय स्थायी समिति द्वारा इस निमित्त अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख स्कोम के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी यंत्र सामग्री प्रौद्योगिकी पार्क एककों में उत्पादित या विनिर्माण उत्पाद-शुल्क माल को लागू नहीं होगी” ।

[फा. सं. 354/80/92-टी आर यू]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 1993

NO. 92/93-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 97/91-Central Excises, dated the 7th October, 1991, namely :—

In the said notification, after the third proviso, and before the explanation, the following paragraph shall be inserted, namely :—

“2. Nothing contained in this notification shall apply to excisable goods produced or manufactured in the Electronics Hardware Technology Parks units under hundred per cent export oriented scheme approved in this behalf by the Inter-Ministerial Standing Committee appointed by the notification of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 117(E), dated the 22nd February, 1993, as amended from time to time.”

[F. No. 354/80/92-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1993

सं. 147/93-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 489 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 89/89-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 346/15/93-टी आर यू]

राजीव शर्मा, अव्वर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 1993

NO. 147/93-CUSTOMS

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 89/89-Customs, dated the 1st March, 1989, namely :—

In the Table annexed to the said notification, Sl. No. 10 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 346/15/93-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

